vinetur

वाइन व्यापार के नियम सरल करने के लिए नौ उत्पादक देश स्टेलेनबॉश में जुटे

वर्ल्ड वाइन ट्रेड ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधियों ने बाजार तक पहुंच, इलेक्ट्रॉनिक लेबलिंग और सीमापार वाइन खेपों को जटिल बनाने वाले प्रमाणन मानकों पर चर्चा की

रविवार, 8 नवंबर 2026



दक्षिण अफ्रीका ने स्टेलेनबॉश में नौ वाइन उत्पादक देशों की बैठक की मेज़बानी की। इसमें प्रतिनिधियों ने वाइन व्यापार की बाधाएं घटाने, निर्यात बाजारों तक पहुंच बेहतर बनाने और इलेक्ट्रॉनिक लेबलिंग तथा प्रमाणन पर काम में तालमेल बिठाने पर ध्यान दिया।

यह बातचीत वर्ल्ड वाइन ट्रेड ग्रुप के तहत हुई, जो उद्योग को प्रभावित करने वाले व्यापार और नियामकीय मुद्दों पर चर्चा के लिए वाइन उत्पादक देशों को एक मंच पर लाता है। स्टेलेनबॉश की बैठक का एजेंडा व्यावहारिक कदमों पर केंद्रित था, जो यह तय कर सकते हैं कि वाइन सीमाओं के पार कैसे पहुंचे—खासकर तब, जब निर्यातकों को हर गंतव्य पर अलग-अलग दस्तावेज़ीकरण, लेबलिंग और बाजार में प्रवेश के नियमों का सामना करना पड़ता है।

बाजार तक पहुंच चर्चा का एक अहम मुद्दा था। वाइन उत्पादकों के लिए पहुंच अक्सर केवल शुल्कों पर ही नहीं, बल्कि आयातक देशों के घरेलू नियमों पर भी निर्भर करती है। इन नियमों में उत्पाद का विवरण, स्वास्थ्य और उत्पत्ति संबंधी जानकारी, आयात मंज़ूरी और तकनीकी मानक शामिल हो सकते हैं। जब एक बाजार से दूसरे बाजार तक आवश्यकताएं व्यापक रूप से अलग-अलग होती हैं, तो उत्पादकों और निर्यातकों को अतिरिक्त लागत, देरी और प्रशासनिक काम का सामना करना पड़ सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक लेबलिंग भी चर्चा में रही। वाइन व्यापार में इस मुद्दे से आम तौर पर QR कोड या इसी तरह के प्रारूपों जैसे डिजिटल साधनों का इस्तेमाल आशय होता है, जिनके ज़रिए उत्पाद की ऐसी जानकारी दी जा सकती है जो अन्यथा केवल भौतिक लेबल पर होती। इसके व्यापक इस्तेमाल के समर्थकों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को अधिक जानकारी मिल सकती है और कई बाजारों में एक ही उत्पाद बेचने वाले उत्पादकों को अधिक लचीलापन मिल सकता है। लेकिन बोतल पर कौन-सी जानकारी देना अब भी अनिवार्य है और किसे डिजिटल प्रारूप में दिया जा सकता है, इस बारे में अलग-अलग देशों के नियमों ने निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा की है।

प्रमाणन बैठक का एक अन्य प्रमुख विषय था। प्रमाणन नियमों में उत्पत्ति, संरचना, उत्पादन विधियों और स्वास्थ्य या सीमा शुल्क संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन से जुड़े दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं। निर्यातकों के लिए प्रमाणपत्रों के प्रारूप या मंज़ूरी की प्रक्रियाओं में मामूली अंतर भी खेपों की रफ्तार धीमी कर सकता है और लागत बढ़ा सकता है—खासकर तब, जब अलग-अलग नियामकीय व्यवस्थाओं वाले कई देशों में वाइन भेजी जा रही हो।

स्टेलेनबॉश की बैठक का महत्व व्यापार नीति के कूटनीतिक पहलू से आगे भी है, क्योंकि वाइन उत्पादक, आयातक, वितरक और खुदरा विक्रेता—सभी इन अंतरों की कीमत चुकाते हैं। अगर प्रमुख निर्यातक देश लेबलिंग और प्रमाणन नियमों में अधिक तालमेल बिठाते हैं, तो इससे अनुपालन लागत घट सकती है और अंतरराष्ट्रीय खेपों का प्रबंधन आसान हो सकता है। व्यापक पेय कारोबार के लिए, कागजी कार्रवाई और दोहराई जाने वाली आवश्यकताओं में कोई भी कमी उत्पादों को आपूर्ति शृंखलाओं से अधिक सुचारु रूप से गुजरने में मदद कर सकती है।

मेज़बान के रूप में दक्षिण अफ्रीका की भूमिका ने दुनिया के स्थापित वाइन उत्पादक देशों में से एक पर ध्यान केंद्रित किया। यह ऐसे समय में हुआ है, जब निर्यातकों पर कड़े नियमन वाले बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहने का दबाव है। नौ उत्पादक देशों की भागीदारी वाली बैठक की मेज़बानी यह भी दर्शाती है कि वाइन व्यापार के मुद्दों को अब केवल कीमत के बजाय तकनीकी समन्वय के ज़रिए तेजी से सुलझाया जा रहा है।

स्टेलेनबॉश में उठाए गए मुद्दे वैश्विक वाइन कारोबार के सामने मौजूद एक व्यापक चुनौती की ओर संकेत करते हैं। उत्पादक ऐसे बाजारों में बिक्री कर रहे हैं जहां उपभोक्ता जानकारी से जुड़े नियम बदल रहे हैं, डिजिटल साधनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और नियामक पता लगाने की क्षमता तथा उत्पाद संबंधी खुलासों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसे माहौल में निर्यातकों को तब फायदा होता है, जब सरकारें आवश्यकताओं को सरल बना सकें या कम से कम विभिन्न बाजारों के नियमों की तुलना आसान कर सकें।

स्टेलेनबॉश में वर्ल्ड वाइन ट्रेड ग्रुप की चर्चा ने इन चिंताओं को एक मंच पर ला दिया। व्यापार बाधाओं, बाजार तक पहुंच, ई-लेबलिंग और प्रमाणन पर ध्यान देकर बैठक ने वाइन कारोबार के उन पहलुओं पर विचार किया, जो अक्सर यह तय करते हैं कि कोई बोतल कितनी जल्दी विदेशी बाज़ार की दुकान तक पहुंचेगी और वहां पहुंचाने में उत्पादक को कितना खर्च करना होगा।